Title: Need to lift ban on the export of cotton-laid.

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली) : माननीय अध्यक्ष महोदया जी, यह पूरे देश को पता है कि 33 प्रतिशत से ज्यादा कपास का उत्पादन केवल गुजरात में होता है। मंहगाई के दौर में किसान को कपास को बोने से लेकर उसके उत्पादन तक खून पसीना एक करना पड़ता है। प्रकृति की मार जैसे - आंधी, तूफान, वर्षा, सूखे इत्यादि घटनाओं एवं अन्य रोगों से मुश्किल से ही कपास सुरक्षित बच पाता है।

गुजरात का कपास इतने उत्तम किस्म का है कि भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार यथा चीन, थाईलैंड, तुर्की, इंडोनेशिया इत्यादि देशों में भी इसकी मांग काफी है। इसका निर्यात होने के कारण किसान भाइयों को 2500 रूपये प्रति टन एक्सपोर्ट डयूटी के साथ अच्छा भाव भी मिल रहा था लेकिन केन्द्र सरकार ने 19 अप्रैल, 2010 को कपास निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इस प्रतिबंध की वजह से हमारे किसान भाइयों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और इस प्रतिबंध के पहले किसानों को जितना भी कांट्रेक्ट मिला था, वह सब अचानक रद्द हो गया है, जिसकी वजह से किसान कर्ज में डूबने की स्थिति में आ गए हैं।

अगर केन्द्र सरकार द्वारा कपास निर्यात पर प्रतिबंध नहीं हटाया गया तो कोटन जिनिंग कमेटी वाले सभी लोग एक अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर उतरने वाले हैं।

यहां मेरी भारत सरकार से मांग है कि यह कपास निर्यात पर प्रतिबंध जो लगाया गया है उसे तुंत हटाया जाये और प्रति टन के हिसाब से जो एक्सपोर्ट डयूटी मिलती थी, उसे वापस किया जाये।